भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 23

मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं

23. श्री महेंद्र भट्टः

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सौर, पवन, जल विद्युत और हरित हाइड्रोजन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) तथा (ख): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

'नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं' के संबंध श्री महेंद्र भट्ट द्वारा पूछे गए दिनांक 21.07.2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 23 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): सरकार, देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विकास और इसकी स्थापना को बढ़ावा देने तथा उसमें तेजी लाने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। सौर, पवन, लघु जल विद्युत और ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में चल रही प्रमुख योजनाओं का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल मिलाकर 288.58 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, जिसमें 162.15 गीगावॉट सौर विद्युत, 57.44 गीगावॉट पवन विद्युत, 57.24 गीगावॉट जल विद्युत और 11.75 गीगावॉट जैव विद्युत शामिल हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, दिनांक 15.07.2026 की स्थिति के अनुसार, 46.95 लाख घर रूफटॉप सौर स्थापनाओं से लाभान्वित हुए हैं और पीएम कुसुम के तहत, घटक ए के तहत 1726.92 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है, घटक बी के तहत 11.49 लाख से अधिक सौर कृषि पंप स्थापित किए गए हैं, और दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, घटक सी के तहत 16.32 लाख से अधिक ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों को सौरीकृत किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, 3000 मेगावाट प्रति वर्ष इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता और 7,56,100 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता आवंटित की गई है । भारत में 11 उर्वरक इकाइयों को ग्रीन अमोनिया (ग्रीन हाइड्रोजन का डेरेवेटिव) के 6,70,000 MTPA के उत्पादन और आपूर्ति के लिए ग्रीन अमोनिया बिक्री और खरीद करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की रिफाइनरियों को आपूर्ति के लिए 30,000 टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और आपूर्ति क्षमता आवंटित की गई है।

अनुलग्नक

चल रही प्रमुख योजनाओं का विवरण

1. पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना (PMSG: MBY) के तहत, 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय से वित्त वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र के एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर सिस्टम्स स्थापित किए जाएंगे।
2. पीएम-कुसुम योजना जिसमें विकेन्द्रीकृत सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों की स्थापना, स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंपों की स्थापना और फीडर-स्तरीय सौरीकरण सहित मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण शामिल है। इस योजना से न केवल किसानों बल्कि राज्यों और डिस्कॉम को भी लाभ होता है। 34,422 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (CFA) परिव्यय के साथ 10,000 मेगावाट विकेन्द्रीकृत सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों और 49 लाख कृषि पंपों की स्थापना/सौरीकरण के लक्ष्य की व्यवस्था है।
3. 40,000 मेगावाट क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के अंतर्गत सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ भूमि, सड़कों, विद्युत निकासी प्रणाली, जल सुविधाओं जैसी अवसंरचना का विकास किया जाता है। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-पैमाने की सौर परियोजनाओं के तेजी से विकास में मदद करती है। इस योजना में 8,100 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) परिव्यय के साथ 40,000 मेगावाट की क्षमता की व्यवस्था है।
4. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (भाग-I और II) में गीगा वाट (GW) स्तर की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना "उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम"। इस योजना में 24,000 करोड़ रुपये के CFA परिव्यय के साथ उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों की पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत विनिर्माण क्षमता स्थापित करने की व्यवस्था है।
5. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के तहत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) में 915 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ऑफ-ग्रिड

सोलर लाइटिंग की व्यवस्था करने का प्रावधान है, जहां ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

6. वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए 2,584.60 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लघु जल विद्युत (SHP) विकास योजना (1 मेगावाट से 25 मेगावाट)। इस योजना का लक्ष्य भारत भर में लगभग 1,500 मेगावाट नई एसएचपी क्षमता स्थापित करना है
7. राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरेवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक ग्लोबल हब बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस योजना में 19,744 करोड़ रुपये के CFA परिव्यय के साथ, वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।
8. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) फेज़ I और II का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम तैयार करना है।

*****